भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-570
बुधवार, 26 जून, 2019/5 आषाढ़, 1941 (शक)

रोज़गार सृजन की निम्न दर

570. श्री ए॰ विजयकुमारः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गत तीन वर्षों में विभिन्न आंकड़े यह दर्शाते हैं कि रोज़गार सृजन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में समाधान/रोजगार में वृद्धि लाने के लिए कोई विशेष कार्य बल बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए गए। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएसओ वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। 2009-10, 2011-12 एवं 2017-18 के दौरान देश में सभी आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात नीचे दिया गया हैः

कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)			
वर्ष	पुरुष	महिला	व्यक्ति
2017-18* (पीएलएफएस)	52.1	16.5	34.7
2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	54.4	21.9	38.6
2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	54.6	22.8	39.2

*(टिप्पणीः *तुलना हेतु, एनएसएस सर्वेक्षणों के पूर्व के दौर के साथ पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)*

(ग एवं घ): रोजगार आंकडों में सुधार के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्य बल की स्थापना की गई। इसने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2017 में प्रस्तुत कर दी है। इसने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अतिरिक्त, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा एक नया समयोपयोगी सर्वेक्षण आयोजित एवं संस्थापित किया जाए। इसने कामगारों की कुछ श्रेणियों पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) जैसे स्रोतों से प्रशासकीय आंकड़े लेने की सिफारिश की।

*****